बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांक : 13:10:400:01:2017 10537 विधि/पटना, दिनांक :– 12/10/17

प्रेषक,

पंकज कुमार (भा0प्र0से0),
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **Cr. Misc. No. 29168/2017 अशोक कुमार सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.10.17 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि SLP (Cr) No. 1779/2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.02.17 को पारित आदेश के आधार पर CJM द्वारा निर्गत Non Bailable Warrant को रद्द कराने के लिए प्रमादी मिलरों द्वारा दायर Cr. Misc. No. 29168/2017 अशोक कुमार सिंह व अन्य 27 वादो को एक साथ Dismissed करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 09.10.17 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार हैः–

"In the opinion of this Court, no notice was required to be issued to the accused persons and no formal order of cancellation of bail was required to be passed by the trial court, as under condition no. (1), it has categorically been held that the accused in all the FIR(s) will ensure that bank guarantee, if not furnished, is furnished and if lapsed, is renewed within a period of one month from today failing which the anticipatory bail/bail granted will stand cancelled. As the petitioners admittedly did not furnish bank guarantee within the period stipulated, their anticipatory bail already granted stood automatically cancelled by virtue of the order of the Supreme Court.

It is not permissible for this Court to modify the directions issued by the Supreme Court.

If the petitioners are aggrieved by the order of the Supreme Court regarding deposit of bank guarantee, the only course left to them is to approach the Supreme Court and till the time the order of the Supreme Court stands, the petitioners, whether they were party before the Supreme Court or not have to abide by its orders.

I would like to observe that in case the petitioners, whose pre-arrest bail stood cancelled, comply with the directions given by the Supreme Court and surrender before the court, they should be granted bail in accordance with law."

अतः अनुरोध है कि वैसे सभी प्रमादी मिलर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गये हैं अथवा नहीं गये हैं, किन्तु वे प्राथमिकी में अभियुक्त (Accused) हैं और उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 28.02.17 के पारित आदेश के बाद **बैंक गारण्टी** निगम के पक्ष में जमा नहीं कराये हैं। उन सभी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Cr. Misc. No. 29168/2017 में दिनांक 09.10.17 को पारित उक्त आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0– Cr. Misc. No. 29168/2017 व अन्य में
दिनांक 09.10.17 को पारित आदेश की प्रति।

विश्वासभाजन
12/10/2017
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।